

24915-

राज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

223/2018/225

गोपाल व/र जितेन्द्र वगैरे

तारीख

2018/00223

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

9A-4

पेशी

श्री गोपाल इकबाल

श्री तुलवीर सिंह चौधरी ने 3

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

10/10/22

गोपाल बनाम जितेन्द्र वगैरेह (2018/00223)
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांत एवं अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से
3 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद
अधिनियम एवं अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांत ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद
अधिनियम निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने
से पूर्व अपीलांत को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस कैम्प कोर्ट सुनवाई नहीं
दिया गया। जिससे अपीलांत कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया और
अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.05.2018 को कैम्प कोर्ट में आदेश पारित
किये थे उस समय केवल रेस्पोंडेन्ट ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित
थे। सर्वप्रथम अपीलांत को उपरोक्त आदेश की जानकारी दिनांक 28.06.2018
को हुयी जब रेस्पोंडेन्ट ने अपीलांत के कब्जे काशत में दखलंदाजी की। जिस
पर अपीलांत द्वारा न्यायालय में अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर उपरोक्त
तथ्यों की जानकारी ली। जहाँ अभिभाषक ने अपीलांत को अवगत करया कि
कैम्प कोर्ट के तहत आदेश पारित किये थे इसलिए आगे अपील करने की
आवश्यकता है। जिस पर नकल प्राप्त होने पर अभिभाषक से सम्पर्क कर यह
अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। माननीय न्यायालय
से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार
किया जाकर अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांत ने अपील पर बहस करते हुए बताया कि
वादग्रस्त आराजीयात को अपीलांत के द्वारा रामदेव से क्रय किया गया था
जिसके पश्चात् से ही वह उपरोक्त आराजीयात पर काबिज काशत चला आ
रहा है परन्तु पश्चात्तवर्ती विक्रय-पत्र जो कि रामदेव की विरासत के आधार
पर हुआ। जिससे रेस्पोंडेन्ट ने रदयं का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा
लिया और वही अपीलांत के कब्जे काशत में दखलंदाजी करने पर आमादा हो
रहे है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए ही दिनांक 12.03.2018 को
प्रार्थी/अपीलांत के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई जिसके
पश्चात रेस्पोंडेन्ट को जवाब हेतु नोटिस जारी किये गए तथा दिनांक 10.05.
2018 को उपरोक्त वाद ग्राम खीरीया में राजस्व लोक अदालत के तहत
प्रस्तुत होने पर बिना अपीलांत को सुने अपीलांत/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को
कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर सारहीन व भारहीन मानते हुए खारिज करने
कानूनी त्रुटि कारित की है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील
अपीलांत स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित
आदेश दिनांक 10.05.2018 को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा
नम्बर 114 रकबा 10 बीघा 18 विस्वा वाकै ग्राम गणेशपुरा तहसील सरवाड़
की ताफैसला मूल वाद तक गौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखने हेतु
उभयपक्ष को पाबंद करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 03 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए बताया कि
अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली में प्रार्थी/अपीलांत को दिनांक 10.05.2018
को अटल सेवा केन्द्र खीरिया में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किये गये
थे वाद तामील पत्रावली में सलंग्न है। अपीलांत का यह कहना की कैम्प कोर्ट
के नोटिस प्राप्त नहीं होना कहना गलत है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में देरी का
उक्त कारण ही अंकित किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05
मियाद अधिनियम को खारिज फरमाया जावे।

राज अदालत प्राधिकारी
अजमेर

सक्राई

223

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2018/225

गोपाल 1/6 जितेन्द्र

तारीख

2018/00223

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

GA-4

पेशी

श्री गोपाल

श्री तुलसी सिंह चौधरी 1/6

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

लगाव

तत्पश्चात अभिभाषक रेस्पोंडेंटस ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने दो प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किये है पहला प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2016 पेश किया तत्पश्चात दिनांक 12.03.2018 को पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त किये है जो विधिक त्रुटि कारित की थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो दिनांक 10.05.2018 जो आदेश पारित किये है विधि सम्मत है इसलिए माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। बाद मनन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण एवं अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्कों के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 14/2018 व प्रार्थना पत्र 106/2016 में वादग्रस्त आराजी समान है किन्तु दोनो प्रार्थना पत्रों में पक्षकार अलग अलग है ऐसी स्थिति में 14/2018 वरुन्वानी गोपाल बनाम जितेन्द्र वगैरह को सारहीन व भारहीन मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की है तथा प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निर्णित नहीं किया गया है। वाद के विचाराधीन रहते हुए विवादित आराजी बाबत वाद की वाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए विवादित आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम गणेशपुरा तहसील सरवाड़ की ताफैसला मूल वाद तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 10.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम गणेशपुरा तहसील सरवाड़ की ताफैसला मूल वाद तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर